MR. CHAIRMAN: Next Question 303.

श्री मोतिउर रहमान: सर, प्रश्न 316 भी इसी तरह का है, इन दोनों को मिला दिया जाए।

श्री सभापति: अभी एक का जवाब आने दीजिए, मैं देख लेता हूं।

Integrated Handloom Cluster Development Programme

*303. MS. PRAMILA BOHIDAR:†
SHRI B.J. PANDA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that handloom sector is the largest source of employment in rural areas, after agriculture;

(b) whether Government have launched the Integrated Handloom Cluster Development Programme for development of this sector;

(c) if so, whether it is a centrally funded project; and

(d) if so, the details of clusters being developed in Orissa and the amount of Central aid since provided to these centres?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SHANKERSINH VAGHELA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Integrated Handloom Cluster Development Programme

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Government of India has launched "Integrated Handloom Cluster Development Scheme (IHCDS)" in the year 2005-06 which is 100% Central Sector Scheme.

(d) Two clusters i.e. Sonepur and Bargarh in Orissa have been approved for their integrated and holistic development and a sum of Rs. 21.05 lakh for each cluster has been released so far to the implementing agencies.

MS. PRAMILA BOHIDAR: Hon. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister what are the basic infrastructures being provided or proposed to be provided in the Integrated Handloom Cluster Development Programme? Are banking finance and marketing facilities being provided to weavers in these clusters? If so, what are the details, State-wise?

†[The question was actually asked on the floor of the House by Ms. Pramila Bohidar.]

श्री शंकर सिंह वाघेला: सर, यह उड़ीसा का क्वैश्चन है, हमने उड़ीसा में दो handloom clusters clear किए हैं - सोनपुर और बाड़गढ़, जिनमें हमने अब तक 21 लाख रुपए दिए हैं और गवर्नमेंट एक cluster के पीछे 2 करोड़ रुपए दे रही है। अगर आपको स्कीम की detail चाहिए, तो मैं पढ़ना ठीक नहीं समझता, लेकिन to provide the development of handloom clusters, इसमें बहुत detail हैं मैं आपको बाद में भेज दूंगा। ये जो weavers के लिए handloom clusters हैं, उन्हें कहीं बाहर न जाना पड़े और एक ही जगह पर उनको इसके लिए जो भी चाहिए, हमने पूरे देश में, सब राज्यों में हमारी टीम भेजी और डाक्टर जैसे किसी बीमारी का analysis करता है, वैसे ही वहां जाकर पूरी इंडस्ट्री का diagnosis करके उस इंडस्ट्री के लिए, handloom weavers के लिए क्या जरूरी है उस हिसाब से हमने 100 Clusters identify किए हैं। उड़ीसा में 6 हैं और दो के लिए तो हमने 21 लाख रुपए दे भी दिए हैं।

MS. PRAMILA BOHIDAR: Is there any scheme to protect the copyright of traditional designs which are being copied by other textile mills? Is the Government aware of the precarious financial condition of the Sambalpur Handloom Cooperative Society which is one of the largest cooperative institutions of weavers in the country? If it is so, what are the steps being taken to improve the situation?

श्री शंकर सिंह वाघेला: सर, handloom के design की कॉपी हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन handloom को powerloom की ओर से कॉपी का जो भय है कि handloom के नाम पर जो भी powerloom का production होता है, जिसको marketing होती है, इसलिए हमने handloom mark का introduction किया है, logo का introduction किया है। प्रधान मंत्री जी खुद आए थे और उन्होंने ही handloom mark introduce किया है। उसका बहुत अच्छा response मिल रहा है। यहां आपने जो co-operative की बात की है, तो यद्यपि यह राज्यों का subject है, फिर भी हमने इतनी co-operative societies को, हमने आन्ध्र प्रदेश को 19.5 करोड़ रुपए दिए हैं, उत्तर प्रदेश को 5 करोड़ रुपए दिए हैं, हमने कर्नाटक को भी 20 करोड़ रुपए दिए हैं। अगर ऐसे apex co-operatives sick हैं, तो उस बुनकर को ठीक करने के लिए, उसका जो कर्ज है उसे active करने के लिए, marketing के लिए या वह जो भी production करता है, उसे ये co-operative societies purchase करें, क्योंकि इनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसमें हमने 2 करोड़ रुपए राज्यों की इस co-operative society को दिए हैं और यह अब ठीक हो रहा है।

SHRI B.J. PANDA: Sir, the hon. Minister has acknowledged that, after agriculture, handloom is the second largest source of employment in the

rural areas; and yet in places like Sambalpur thousands of villagers are today on the streets and they have taken to pulling rickshaws because they are no longer able to make a living. In the light of this, this allocation of Rs. 21 lakhs sounds very meagre. I would like the hon. Minister to tell us as to what is that they are supposed to provide and how many weavers they are supposed to help. How does this compare with the other clusters that have been set up in other parts of the country? Is this, on an average, a typical figure, or, is it particularly low? How many weavers are they supposed to help?

श्री शंकर सिंह वाघेला: चेयनमैन सर, यह बहुत अच्छी बात है। Traditionally, उस समय से, जब से Indian Culture है, तब से handloom हमारे घर-घर में होता रहा है। यह financially, economcally viable नहीं है, इसलिए पूरी इंडस्ट्री धीरे-धीरे Powerloom में, जैसे महाराष्ट्र में और बाकी जगह भी, divert होने लगी है। मैं आपको यह रेकार्ड पर कहना चाहूंगा कि 2003-04 से पहले handloom production minus में था, कम था; 2004-05 का Production 4 per cent बढ़ा है; 2005-06 में पूरे देश में handloom का prodcution 8 per cent बढ़ा है। इतना ही नहीं, हमने इतनी नई स्कीम्स भी introduce की हैं, जिन स्कीम्स के तहत कई नए weavers की, जैसे महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना है या हमने इनके medical health के लिए स्कीम introduce की है, जिसमें handloom weavers को कम-से-कम figure देनी पड़े और काफी लाभ मिले। अभी जो handloom cluster की बात है, वह 100 से लेकर 5,000 looms के लिए अलग-अलग, जैसे यूपी में बनारस है, तो 50,000 looms हैं , लेकिन कहीं 100 हैं, कहीं 200 हैं, तो 100 से लेकर 5,000 looms का एक cluster develop करने की यह स्कीम है। हम एक को 2 करोड़ रुपए देते हैं। हमने पूरे देश में 100 handloom clusters identify किए हैं। All over, 1995-96 का जो figure हैं, पूरे देश में तकरीबन 450 से ऊपर clusters हैं, लेकिन इसे identify करके handloom weavers को एक जगह cluster की स्कीम का लाभ मिले, इसलिए हमने पूरी स्कीम introduce की है और as early as possible, उसका लाभ भी मिलेगा, अभी यह primary है।

श्री रूद्रनारायण पाणि: सभापति महोदय, समेकित हथकरघा समूह विकास कार्यक्रम 2005 से बढ़ रहा है। वर्ष 2006 में स्थायी समिति में भी इस पर चर्चा हुई थी और कहा गया था कि क्लस्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। महोदय, उड़ीसा में 2 कलस्टर समूह बताए गए हैं–एक सोनपुर में और दूसरा बरगढ़ में जिसे हिंदी में बाड़गढ़ कहा गया है वह अंग्रेजी में Bargarh होगा और वह संशोधित हो जाएगा, लेकिन इस विषय को भी उठाया जाना चाहिए। महोदय, सोनपुर और बरगढ़–दोनों उड़ीसा के पश्चिमी हिस्से में हैं और छत्तीसगढ़ से सटे हुए हैं। महोदय, पूरा-का-पूरा उड़ीसा पिछड़ा हुआ है, इसलिए उड़ीसा का जो तटवर्ती क्षेत्र है, उसमें कटक जिले में नुआपाटना एक स्थान है जहां

बहुत जगह साड़ी बनती है। हमारे वहां उसे पाट कहते हैं महोदय, नुआपाटना में एक क्लस्टर के बारे में मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था क्या माननीय मंत्री महोदय उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र के कटक जिले के नुआपाटना में नया क्लस्टर बनाने के बारे में विचार करेंगे? दूसरे, देशभर में क्लस्टर्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

महोदय, मंत्री महोदय गुजरात से आते हैं। गुजरात के सूरत शहर में 8 लाख उड़िया रहते हैं और हथकरघा सेक्टर में काम करते हैं। मंत्री महोदय कृपा करके सूरत के उन 8 लाख उड़िया बुनकरों के बारे में भी step लें।

श्री शंकर सिंह वाघेला: चेयरमैन सर, माननीय सदस्य की बात सही है, सूरत में बहुत से उड़िया लोग रहते हैं। जब वहां फलड आया था तो दूसरे ही दिन हम वहां गए थे, सभी को मिले, उनके खाने-पीने की व्यवस्था की। मिनिस्ट्री की ओर से हम ने स्कीम, as an industrial package clear कर दी है और थोड़े दिनों में वह ऑफिसियली डिक्लेअर हो जाएगी। महोदय, उड़ीसा में दो प्राइमरीज में किए हैं–इसमें बौद्ध, बुसानी, बुटपाली को मिलाकर एक है और दूसरा बड़म्बा में है जिसमें मनिमब्धा, मुक्तानगर है, तीसरा बहरामपुर में आस्का, पीतल included है, चौथा जगतसिंह पुर है जिसमें बग्वाद, कॅडाल, जयपुर है, पांचवां फकीरपुर और छटवां पटनागर है। इस तरह ये 6 क्लस्टर्स उड़ीसा की लिस्ट में हैं। दो को पैसे दे दिए हैं, बाकी 4 को भी as early as possible होगा, करेंगे। महोदय, पूरे देश में 100 की लिस्ट है और जो एम॰पीज॰ अपने इलाके की चाहें, मैं जिलों के हिसाब से आपको लिस्ट भेज दूंगा कि कौन-कौन से क्लस्टर्स, कौन-कौन से जिले में include किए हैं।

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Chairman, Sir, as the hon. Member has said, there is no insurance cover for the handloom sector. The States are not implementing the insurance scheme. Even the cooperative housing scheme is not being implemented for handloom weavers. Their income is also very meagre, even through the cooperative societies. Sir, the States are not getting adequate funds for strengthening the cooperative societies and the handloom sector. Will the Government reorient the policy and give more funds to the States so that the handloom sector can be strengthened?

श्री शंकर सिंह वाघेला : सर, पूरी implementing agency राज्य सरकारें और हमारी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसायटीज हैं। फिर भी जैसाकि मैंने फरमाया आंध्र प्रदेश को साढ़े 19 करोड़, यू॰पी॰ को 5 करोड़ और कर्नाटक को 20 करोड़ दिए हैं। इस तरह जहां-जहां लगा कि पैसे की जरूरत है, वहां देने के बाद काफी आक्सीजन मिली है और वीवर्स को फायदा हुआ है।

SHRI V. NARAYANASAMY: It is very meagre.

श्री शंकर सिंह वाघेला: सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों को भी इसकी चिंता करनी चाहिए। हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है और न ही हैंडलूम की वह जिम्मेदारी है, ऐसी मॉरल रेस्पॉंसिबिलिटी है, फिर भी इनके लिए जो नई स्कीमें हमने इंट्रोड्यूस की हैं, उनमें हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम और महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना है। हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम में वीवर्स को सिर्फ 80 रुपए प्रीमियम देने हैं और इसमें तकरीबन 3 लाख वीवर्स ने इसका लाभ लिया है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना में वीवर्स को 200 रुपए देने हैं और इसमें तकरीबन 2 लाख 77 हजार वीवर्स ने इसका लाभ लिया है। ये काफी अच्छी नई-नई स्कीमें हैं, जिनमें स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीस या वह इनक्लूड न हो, ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस से हैं। उनकी इम्प्लीमेन्टेशन में प्रोब्लम्स होती हैं, इसलिए हैंडलूम क्लस्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस से hundred per cent direct लाभ मिलेगा, जिसमें राज्य सरकार का कोई इनवॉल्वमेंट नहीं होगा। ...(व्यवधान)... हाउसिंग स्कीम में भी वह हो रहा है, लेकिन इसमें राज्य सरकारों की ओर से जो प्रोपोजल्स आते हैं, उन प्रोपोजल्स के हिसाब से हैंडलूम मिनिस्टर को देखना है कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है।

Transport subsidy to tea exporters

*304. DR. M.A.M. RAMASWAMY: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the South Indian Tea Exporters Association has requested the Union Government for extension of the transport subsidy;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken by the Central Government in this regard so that the Tea exporters from South India are able to compete with neighbouring countries?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COMMERCE, MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI JAIRAM RAMESH): (a) No such request has been received by the Government from the South Indian Tea Exporters Association.

(b) and (c) Do not arise.

DR. M.A.M. RAMASWAMY: Sir, as the House is well aware, India was ranked as one of the top tea exporters in the past. But, now this rank has been snatched away by smaller countries like Kenya, Sri Lanka etc. The tea export from India is declining every year. After the disintegration of former Soviet Union, the situation has further deteriorated. I would like to know what steps have been taken from the Government side...(*Interruptions*)